

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. : 05/2022 (राजस्व अपील)

GCMS NO : 2022/36

अनवान

ग्रामवासी गांव बटेरी, तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर जरिये प्रतिनिधी:-

1. श्री गेहरीलाल पिता धूलजी ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री सोहनलाल पिता वना ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री प्यारचन्द्र पिता मगनलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. श्री उत्तम पिता मिठालाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
2. श्री नीलकंठ पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. श्री कन्हैयालाल पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. श्री विष्णु पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
5. श्री पप्पू पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
6. श्री हीरालाल पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
7. श्री रमेश पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती गीता पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
9. श्रीमती सुशीला पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
10. श्रीमती प्यारीबाई पिता गेहरीलाल ब्राह्मण निवासी बटेरी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री रमेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 10।

प्रा.पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम

1970 बाबतु निरस्त कराये जाने आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976



*** निर्णय ***

दिनांक 19-04-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा बटेरी तहसील गोगुन्दा में साबिक आराजी नम्बर 1503 रकबा 5 बीघा जमीन स्थित है जिसके हाल आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 1.0800 हेक्टेयर बने है। वक्त आवंटन विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी सरपंच थे तथा अपने सरपंच पद का दुरुपयोग करते हुए कथित जमीन का आवंटन अपने नाम पर करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष पेश किया। विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी वक्त आवंटन काश्तकार नहीं थे तथा वे सरपंच के पद पर कार्यरत थे एवं आवंटन सलाहकार समिति के स्वयं सदस्य थे तथा स्वयं सदस्य होते हुये स्वयं को उक्त भूमि का आवंटन कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि वह पद पर आसीन थे एवं भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में नहीं आते थे व उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन सरपंच पद से आयी आमदनी से ही चल रहा था उन्होने कभी भूमि पर काश्त नहीं की। भूमि आज भी पहाड के रूप में ही है। कथित आवंटन अन्य गांव में स्थित जमीन का करवाया, जबकि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी अन्य गांव ब्राह्मणों का कलवाना के निवासी थे एवं उक्त तथ्य को छिपाकर अन्य गांव की जमीन का आवंटन अपने नाम पर कराने हेतु कार्यवाही की, जबकि जिस गांव में जमीन स्थित है उस गांव के भूमिहीन व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु उक्त प्रकरण में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने स्वयं के ना पर जो आवंटन कराने का आदेश पारित करवाया वह आदेश स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। जमीन की किस्म पहाड है तथा पटवारी हल्का ने भी यही रिपोर्ट की है। इस पर विपक्षी या उनके पिता गेहरीलाल जी का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह जमीन गांव के मवेशियों के चरने के काम में आ रही है। कथित जमीन के सम्बन्ध में विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी व विपक्षीगण ने कभी भी आवंटन के शर्तों की पालना नहीं की है, जबकि कथित जमीन के सम्बन्ध में पहले वर्ष आधी जमीन पर काश्त किया जाना आवश्यक था व दूसरे वर्ष पूरी जमीन पर काश्त की जाना आवश्यक था, अगर दोनो वर्षों में पूरी जमीन पर काश्त नहीं की गई है, तो उसके लिए तहसीलदार साहब से स्वीकृति होकर एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, परन्तु इस मामले में विपक्षीगण तथा उनके पिता गेहरीलाल जी ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त योग्य नहीं बनाया है, न ही काश्त की है। इस कारण कथित आवंटन काबिल निरस्त के है। कथित आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है, न उद्घोषणा पत्र की तामील ही कराई गई है। इस कारण कथित आवंटन धारा 60 व 61 भू राजस्व

अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के विपरीत होने से कथित आवंटन इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। कथित आवंटन के पूर्व नियम 4, 5, 6 की पालना नहीं की गई है। आवंटन कमेटी के सदस्य होकर भी अपने नाम आवंटन कराना स्पष्ट रूप से फ़ॉड व मिसरिप्रजन्टेशन से कराया गया प्रकट होता है। उक्त आराजी पर गांव के मवेशी चरते हैं तथा यह सार्वजनिक रूप में काम आ रही है। उक्त आवंटन का दाखला/नामान्तरकरण प्रथम बार सन् 1994 में अपने नम पर दर्ज करवाया। इसके बाद सन् 1999 में जमीन पर आवंटन शर्तों की पालना किये बिना पटवारी हल्का से मिल मिला खातेदारी अधिकार धोखे से प्राप्त कर लिये। ऐसे धोखे से कारित आवंटन को खारिज करने के लिए कोई समय सीमा मुकर्रर नहीं है। इस कारण उक्त आवंटन को खारिज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् आवन्टन निरस्ती का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1976 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे तथाकथित जमीन को पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता सुरेश चन्द्र त्रिवेदी द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षीगण के पिता गेहरीलाल जी का सरपंच होना स्वीकार है विपक्षीगण गांव बटेरी में निवास करते है इसी पते पर विपक्षीगण की तामील होने से न्यायालय में उपस्थित हुए है। विपक्षीगण के पिता मिथ्या तथ्यों का संकलन कर बेबुनियाद आधारों पर विपक्षीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजी की किस्म बीड अंकित कर रखा है। विपक्षीगण के पिता द्वारा आवंटन के नियमों की पूर्णरूप से पालना की गयी है। आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा आवंटन के नियमों को ध्यान में रखते हुए आवंटन किया है, किसी प्रकार से फ़ॉड एवं मिसरिप्रजन्टेशन नहीं हुआ है। आवंटित भूमि का किसी प्रकार से सार्वजनिक रूप से उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थीगण ने मिथ्या अंकन किया है इसलिए आवंटन किसी भी दृष्टि से खारिज फरमाये जाने योग्य नहीं है। विपक्षीगण के पिता द्वारा किसी को धोखा देकर आवंटन नहीं करवाया है बल्कि विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन हुआ है तथा भूमि का आवंटन के नियमों की पूर्णरूप से पालना करने की वजह से खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि दर्ज की है। **विशेष उत्तर** पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण के पिता को लगभग पिछले 45-47 वर्ष पूर्व आवन्टन हुआ तथा विपक्षीगण के जीवित काल में उनका आधिपत्य रहा, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात

विपक्षीगण का आधिपत्य रहा और आवंटन के नियमों की पालना की जाने की वजह से आवंटित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त आराजी वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम पर नहीं होकर ईश्वरसिंह पिता शिवसिंह, किशनसिंह पिता भंवरसिंह, गणपतसिंह पिता दलपतसिंह, जीवनसिंह पिता हरीसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता उदयसिंह व हरिश कुमार पिता बाबूलाल के नाम पर अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अवधि पर्यन्त होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है। इसलिए उपरोक्त समस्त तथ्यों को मद्देनजर फरमाते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थना हे कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर खारिज फरमाया जावे। प्रकरण मे जवाब विपक्षीगण प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 09/1976 तलब की जाकर प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। बहस प्रारंभ करते हुये प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज मय नजीर RBJ(7)2000 page 547, RBJ(21)2014 page 120, RBJ(13)2006 page 168, RRT2021(1) page 124, RRT2005(1) page 83, RRT2007(2) page 1048 पेश कर निवेदन किया कि आवंटन के समय गेहरीलाल सरपंच थे। जवाब में स्वीकार किया है। आवंटन समिति के सदस्य थे। जमीन किस्म बीड है नाकाबिल काश्त है। नियम 4,5,6 की पालना नहीं हुयी हैं नामान्तरकरण 1994 में दर्ज करवाया तथा 1999 में खातेदारी दर्ज हुयी। जिस गांव में आवंटन हुआ उस गांव के निवासी नही थे। ब्राह्मणों के कलवाना के निवासी थे तथा आवंटन बटेरी ग्राम में हुआ है। आवंटन निरस्त किया जावे। आवंटन के समय के नक्शे एवं वर्तमान नक्शे में अन्तर है। 5.6.1976 को आवंटन हुआ तथा 03.05.1977 एक साल बाद कब्जा सिपूदगी बनी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं दस्तावेज मय नजीर RRT2008(2) page 834, RRT2018(2) page 1007, RRT2007(1) page 19, RRT 2007(2) page 1240, RRT2019(2) page 838 पेश कर निवेदन किया कि 47 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ था। प्रार्थना पत्र में आराजी नम्बर वर्तमान नम्बर लिखे हे उनका मैं खातेदार नहीं हूं तथा जिनके नाम खातेदारी है वे पक्षकार नही है। कब्जा देने में देरी होना हमारे वश में नही होता है। 14(4) का प्रार्थना पत्र खातेदार पर मेन्टेनेबल नहीं है। RRT2008(2) page 834 सीआरपीसी 96 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। रेग्यूलर दावा पेश किया जाना चाहिए था। 50 साल में रास्ते बदल गये है आवंटन यथावत रखा जावे। जवाबुल

जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पेश करने में कोई समय सीमा नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 96 का प्रावधान अपील पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति आवंटन खारिज हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। अतः आवंटन खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षीगण के जवाब, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टान्त आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। प्रार्थीगण का तर्क है आवंटन के समय प्रार्थी गेहरीलाल स्वयं सरपंच होकर आवंटन समिति के सदस्य थे, आवंटन समिति के सदस्य होने के नाते उन्होंने तथ्यों को छुपाकर अपने नाम जमीन आवंटन करवा ली है जो कि विधि विरुद्ध होने से आवंटन निरस्त किया जाने की प्रार्थना की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि आवंटन हेतु आवेदन श्री गेहरीलाल पिता उंकार ब्राह्मण द्वारा किया गया है। वर्तमान में गेहरीलाल जी की मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रकरण में गेहरीलाल के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार आराजी नम्बर 2665/2228 रकबा 0.0600 हे. भूमि श्री ईश्वरसिंह पुत्र शिवसिंह चुण्डावत, श्री किशनसिंह पुत्र भंवरसिंह चदाणा, श्री गणपतसिंह पुत्र दलपतसिंह, श्री जीवनसिंह पुत्र हरिसिंह, श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र उदयसिंह एवं श्री हरिश कुमार पुत्र बाबुलाल के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार है। अपीलाण्ट द्वारा वर्तमान के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वर्तमान के खातेदारों को बिना सुने कोई आदेश पारित किया जाता है तो खातेदारों के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रहा प्रश्न कि आवंटन कमेटी के सदस्य होते हुए गलत आवंटन कराने के सम्बन्ध में राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 (1) के प्रथम परन्तुक अनुसार (परन्तु यह और कि जहां सलाहकार समिति के किसी सदस्य का किसी आवेदक में उसके सम्बन्धी होने के कारण या अन्यथा कोई हित हो वहां ऐसा सदस्य समिति की बैठक में भाग नहीं लेगा।) उक्त बिन्दु सरकार के आदेश प.6(12)राज/6/92/32 दिनांक 06.12.1996 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है जो राजपत्र में 4(गजट)(1) दिनांक 20.09.2000 से प्रकाशित किया गया है। प्रार्थी की मूल आपत्ति सदस्य होते हुए आवंटन कराने की है, इसके सम्बन्ध में उक्त प्रावधान आवंटन के बाद में जोड़ा गया है। उक्त आवंटन दिनांक 05.06.1976 को किया गया है उस समय यह प्रावधान लागू नहीं थे। उक्त भूमि गेहरीलाल को आवंटन होने के पश्चात उन्हें खातेदारी अधिकार मिल गये जिस कारण उक्त भूमि को अन्य खातेदारों को हस्तान्तरित भी कर दी गई है। वर्तमान में उक्त भूमि के गेहरीलाल व उसके वारिसान खातेदार नहीं होकर अन्य खातेदार है, जिनको उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसी स्थिति में बिना खातेदारों को सुने खातेदारों

के विरुद्ध कोई निर्णय पारित किया जाता है तो खातेदारों के साथ न्याय नहीं होगा। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आये है। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 अन्तर्गत नियम 14(4) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय को मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर